(b) whether it is also a fact that whereas readers in the University of Delhi get promotion as professor after ten years of services, the senior lecturers/readers of colleges taking classes in Delhi University, remain as such despite the fact that many of them are much senior in the grade as compared to their counterparts in the university departments; and

(c) if so, what action Government propose to take to remove this anomaly?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA) : (a) The University of Delhi has informed that some teachers of the colleges are also taking classes in some Departments of the University under cooperative teaching programme.

(b) Those Readers in Delhi University who opted for the Merit Promotion Scheme, 1983 of University Grants Commission got promotion as Professor after ten years of service since the scheme was applicable only to university appointed teachers.

(c) The Government has since introduced a new Career Advancement Scheme in 1987 which is applicable to teachers in the Universities as well as colleges.

Expenditure on Primary Education

1636. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that compulsory primary education is one of the requisites for total literacy in the country;

(b) whether it is also a fact that percentage of expenditure on primary education has declined from 55 percent in first plan to 29 percent in the Seventh Plan;

(c) if so, what are the reasons of this decline; and

(d) the corrective steps being taken in this direction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) Universalisation of Elementary Education is required for total literacy.

(b) to (d) The Plan expenditure (Centre & States/UTs) on Elementary Education as percent of total Plan expenditure on education was 55.6% in the First Plan which declined to 29.6% in the Sixth Plan and thereafter rose to 37.7% in the Seventh Plan and further to 45.6% in the Eigth Plan. In quantitative terms, the outlay for Elementary Education in the Eigth Plan is Rs. 8,936.46 crore which is 105 times the expenditure on Elementary Education in the First Plan.

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शोध परियोजना

1637. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के लिये फोटो असिस्टेन्ट वाटर स्पिलिंग यूजिंग फन्कशनल पॉलीमर पावर शोध परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और यह धनराशि कब स्वीकृत की गई थी;

(ग) इस शोध परियोजना के लिये क्या समय सीमा निश्चित की गई है;

(घ) क्या समय सीमा पूरी होने के बारे में ब्यौरा प्राप्त हो गया है;

(ङ) क्या परियोजना हेतु खरीदे गये उपस्करों को परियोजना का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग को प्रयोग हेतु सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या परियोजना का कार्य पूरा होने के पश्चात् इसके निदेशक को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्राथमिक शिक्षा हेतु विदेशी सहायता

1638. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु कितनी विदेशी सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है और अब तक प्राप्त हो चुकी विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या क्या हैं जहां उक्त सहायता के साथ इस परियोजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त परियोजना हेतु राज्यों और जिलों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) क्या सहायता प्रदान करने वाले देशों द्वारा इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; यदि नहीं, तो इन मानदण्डों का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी कौन-कौन हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्राचलों (पैरामीटर) के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए विदेशी सहायता मांगी जाती है । ये प्राचल निम्नलिखित हैं :—

—विदेशी वित्तपोषण शिक्षा के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे अतिरिक्त के रूप में होना चाहिए,

—परियोजनाएं राष्ट्रीय नीतियों, कार्यनीतियों तथा कार्यक्रमों के पूर्णतया अनुरूप हों,

—परियोजना तैयार करने का दायित्व केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के ऊपर होना चाहिए,

—परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया क्षमता तैयार करने की होनी चाहिए, अर्थात् परियोजनाएं नवाचारी सिद्धान्तों पर तैयार की गई हों तथा इसमें जनता की भागीदारी, शिक्षा की गुणवत्ता और समानता में सुधार तथा सुविधाओं में पर्याप्त मात्रा में स्तरोन्नयन पर बल हो ।

इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विदेशी सहायता प्राप्त बुनियादी शिक्षा परियोजनाएं बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पहले से ही चल रही हैं । बिहार शिक्षा परियोजना को यूनिसेफ से 180 करोड़ रु० की सहायता प्राप्त है, राजस्थान में लोक जुंबिश परियोजना को 1992—94 के लिए 9 करोड़ रु० एस० आई०डी०ए० से सहायता प्राप्त है तथा उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना को विश्व बैंक से सात वर्ष की अवधि के लिए 633.36 करोड़ रु० की सहायता प्राप्त है ।

जिला विशिष्ट आयोजना और पृथक-पृथक लक्ष्य निर्धारण के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की कार्यनीति को कार्यरूप देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना, 1992 को ध्यान में रखकर अभी हाल ही में "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" नामक एक नया कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे जिलों को चुना गया है जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा जहां सपूर्ण साक्षरता अभियानों से प्रारंभिक शिक्षा के लिए मांग सृजित हुई है । कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिए असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश नामक सात राज्यों के 42 जिलों को चुना गया है । इस कार्यक्रम को वित्तापोषित करने के लिए अनेक बहु-पक्षीय